रेलवे सेवाओं में हरिजनों और अनुसूचित जातियों के कर्मचारी

3162. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे सेवाओं में हरिजन और अन्य अनुसूचित जातियों के कितनी कर्मचारी हैं ;

(ख) उनमें कितने अधिकारी हैं तथा कितने अन्य कर्मचारी हैं ; और

(ग) उनके लिये कुल कितने पद आरक्षित हैं और सब आरक्षित पदों पर हरिजनों तथा अन्य अनुसूचित जातियों के लोगों को कब तक नियुक्त किया जायेगा ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) 2,34,237.

(ख) प्राधिकारी 258
अन्य 2,32,979

(ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आरक्षित पदों की संख्या वर्ष में भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या पर निर्भर करती है । जो पद बिना भरे रह जाते हैं, उन्हें अगले दो भर्ती वर्षों में आगानीत कर लिया जाता है । इस समय 4,481 स्थानों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों को लगाना बाकी है । इस कमी को पूरा करने में कुछ समय लगेगा क्योंकि भर्ती पर पाबन्दी लगी हुई है और फालतू कर्मचारियों को भी समाहित करना है । इसके अलावा, आरक्षित रिक्तियों को भरना अनुसूचित जातियों को भरना अनुसूचित आदिम जातियों के उपयुक्त उम्मीदवारों की उपलब्धता पर भी निर्भर करता है ।

रामपुर से हल्द्वानी तक बड़ी रेलवे लाइन

3163. **श्री शिव कुमार शास्त्री** :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री शिवचरण लाल :

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रामपुर से हल्द्वानी तक बड़ी रेलवे लाइन बिछाने के निर्णय को कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ;

(ख) इस परियोजना को पूरा करने में कितना समय लगेगा ;

(ग) क्या नई रेलवे लाइन का सर्वेक्षण का काम पूरा कर लिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो वह रेलवे लाइन किन-किन स्थानों में से होकर जाएगी ?

रेलवे मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग). 13-2-1969 को इस लाइन के लिए फिर से यातायात सर्वेक्षण करने की मंजूरी दी गई थी । सर्वेक्षण पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा किया जा रहा है और अक्टूबर, 1969 तक इसके पूरा हो जाने की आशा है । सर्वेक्षण पूरा हो जाने और रेलवे बोर्ड द्वारा सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच कर लेने के बाद इस लाइन के निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव पर आगे विचार किया जायेगा ।

(घ) प्रस्तावित मार्ग, जिसका कि पहले सवक्षण किया जा चुका है, रामपुर, बिलासपुर और रुद्रपुर से होकर जाता है ।

Views of Japaneses Delegations regarding Setting up factories in India

3164. SHRI MUHAMMAD SHERIFF: Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the Japanese Delegation, which visited New Delhi, had stated that in Malaysia it takes two years to start a factory, whereas in India it takes two years to get permission to start a factory ; and

(b) in view of the above, whether Government would change the decision making process in the country for the better development of industries ?